



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252331
CG-DL-E-24022024-252331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945

No. 804]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 843(अ).—यतः, मै. सी.सी.एल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य में कुव्वाकोल्ली गांव, वारादायापलेम (मंडल), चित्तूर जिला में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.1035(अ)	31.03.2017	11.879	11.879
(ii)	का.आ.2009(अ)	21.05.2021	1.895	13.774

और यतः, मै. सी.सी.एल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 1.514 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उनके पत्रों सं. 4859/इन्फ्रा/ए3/2016 दिनांक 14 जुलाई, 2016 एवं 4859/इन्फ्रा/ए3/2016 दिनांक 30 मई, 2023 के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

और यतः विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.514 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। अनधिसूचित क्षेत्र 1.514 हेक्टेयर का उपयोग भविष्य में केवल औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.514 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 12.260 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	कुव्वाकोल्ली	276/2ए	0.259
2.		276/2बी	0.142
3.		276/2सी	0.421
4.		276/2डी	0.433
5.		276/2इ	0.259
कुल			1.514
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			12.260

[फा. सं. एफ.1/32/2016-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 843(E).—Whereas, M/s. CCL Products (India) Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Agro based Food Processing at Kuvvakolli Village, Varadaiahpalem (Mandal), Chittoor District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table:-

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O.1035(E)	31.03.2017	11.879	11.879
(ii)	S.O.2009(E)	21.05.2021	1.895	13.774

AND, WHEREAS, M/s. CCL Products (India) Ltd has now proposed for de-notification of 1.514 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Andhra Pradesh has given its approval to the proposal vide letters No. 4859/Infra/A3/2016 dated 14th July, 2022 and 4859/Infra/A3/2016 dated 30th May, 2023;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.514 hectares of the Special Economic Zone. Further, the de-notified area 1.514 Ha will be used in future for industrial purpose only;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.514 hectares, thereby making resultant area as 12.260 hectares. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
1.	Kuvakolli	276/2A	0.259
2.		276/2B	0.142
3.		276/2C	0.421
4.		276/2D	0.433
5.		276/2E	0.259
Total			1.514
Grand total area of SEZ after above deletion			12.260

[F. No. F.1/32/2016-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.